साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 2-8 दिसंबर 2024 वर्ष-10, अंक-33
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8, मूल्यः- 2 रुपए

एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च की बेड़िया मंडी, निमाड़ी मिर्च से लाल

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित बेड़िया में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च की मंडी है। इस मंडी में लाल मिर्च बेचने और खरीदने के लिए देशभर के किसान पहुंचते हैं। बेड़िया मिर्च मंडी विशेष तौर पर निमाड़ी लाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निमाड़ के मिर्च की मांग पूरी दुनिया में है। हर साल यहां लाखों क्विंटल लाल मिर्च आती है, जो कि देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट होती है। यह मंडी 21 एकड़ में फैली हुई है। बेड़िया मंडी में इस साल अभी तक 77,507 क्विंटल मिर्च मंडी तक पहुंच चुकी है। इस मंडी में 400 से अधिक व्यापारी हैं, जो किसानों से उनकी मिर्च को खरीदते हैं।

हर साल महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात और अन्य प्रदेशों से व्यापारी इस मंडी में पहुंचते हैं। अकेले खरगोन जिले में ही 50 हजार हेक्टेयर में निमाड़ मिर्च की खेती होती है। इस मंडी से करीब 10 हजार मजदूर काम करते हैं।

-किसान नई फसल की आवक शुरू होते ही अपनी मिर्च लेकर आए और व्यापारियों को बेचा
-दावाः हर साल महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से 15 से अधिक व्यापारी मंडी में पहुंचते हैं

निमाड़ क्षेत्र में इन किस्मों की होती है खेती

आसपास के जिलों में काशी अनमोल, अर्का सुफल, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, काशी अर्ली, काशी सुर्ख, अर्का मेघना, अर्का स्वेता, अर्का हरिता, नवतेज, माही 456, माही 453, सोनल, एचपीएच-12, रोशनी, शक्ति 51 आदि किस्मों की खेती किसानों द्वारा की जा रही है। बीते वर्ष 2022-23 में रकबा 46556 और उत्पादन 139668 मीट्रिक टन रहा।

गुंटूर में है देश की सबसे बड़ी मंडी

एशिया की पहली सबसे बड़ी मिर्च मंडी की बात करें तो, वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में है। गुंटूर की मंडी को मिर्ची यार्ड भी कहा जाता है। इस मंड़ी में आने वाली लाल मिर्चों का निर्यात कनाडा, यूरोप और एशिया के कई देशों में किया जाता है। खरगोन जिले की और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की लाल मिर्च की मांग पूरे देश में हैं।

बीज ग्राम योजना के तहत दिए जाने वाला गेहूं निकल रहा घटिया

बीज के नाम पर किसानों से छल

» कृषि विभाग किसानों को दे रहा गेहूं की 8737 (अनमोल) किस्म

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि विभाग ने अनुदान के नाम पर किसानों को घटिया गुणवत्ता का बीज बांट दिया है। बीज ग्राम योजना के तहत उन्नत किस्म का बीज उत्पादित करने कें लिए यह बीज इस महीने की शुरुआत में प्रदेश भर के किसानों को उपलब्ध कराया गया। किसानों ने बोवनी के लिए इसके बोरे खोले तो उन्हें घुना हुआ गेहूं मिला है। भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित प्रदेश के कई जिलों से इसकी शिकायत आ रही है। दरअसल, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग बीज निगम से गेहूं के बीज की 8737(अनमोल) किस्म अन्नदाताओं के लिए उपलब्ध करवा रहा है। सभी पंचायतों में कृषि विस्तार अधिकारियों के जरिये यह बीज किसानों को अनुदान पर दिया गया। भोपाल के ग्राम भैंरोपुरा, डोबरा, खजूरी कलां सहित अन्य गांव के छोटे किसानों ने कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक) से करीब 1200 रुपये के हिसाब से आठ हजार 737 बोरियां ली थी। विभाग द्वारा भेजे गए बीज पर किसानों को भरोसा था, लेकिन जब उन्होंने बोवनी के समय इसे खोलकर देखा तो वह पूरा खराब निकला। गेहूं में घुन लग चुका था, उनमें कीड़े पड़ गए थे। किसानों ने कृषि विभाग के अफसरों से मिलकर इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनको दूसरे बीज का विकल्प भी नहीं मिला है। बोवनी का समय बीत रहा है, इसलिए किसान परेशानी में हैं।

मात्रा में भी हेरफेर

बताया जा रहा है कि किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा गांव के किसानों को बेहतर किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए विभाग बीज निगम से गेहूं लेता है और फिर बीज ग्राम योजना के तहत सभी कृषि विस्तार अधिकारियों को करीब 50-50 बोरियां उपलब्ध कराता है। यह अधिकारी प्रति किसान को सिर्फ 40 किलोग्राम बीज यानी एक बोरी देता है।

हर वर्ष बढ़ रहा गेहूं का रकबा

मध्यप्रदेश में गेहूं की फसल बोवनी का रकबा हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। पिछले सालों का रिकार्ड देंखे तो अधिकतम 95 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई थी। अब इस बार 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बढ़कर 110 लाख हेक्टेयर पहुंचने की संभावना है।

किसान बोले, बोवनी के लिए करनी पड़ रही जद्दोजहद

गेहूं की बोवनी के लिए कृषि विस्तार अधिकारी से हमने चार नवंबर को 8737 बीज खरीद था। हमने पूरी तैयारी कर ली थी,जैसे ही बोवनी के लिए बोरियां खोलकर देखीं तो कीड़े रेंग रहे थे। हाथ में बीज लिया तो आटा लग रहा था। ऐसे में अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है। अब तक बीज नहीं मिला है।

- अजय सिंह ठाकुर, किसान, ग्राम डोबरा जागीर

पंचायत से कृषि विस्तार अधिकारी ने जो बीज दिया है। उसकी बोरी खोलने पर वह घुन लगा हुआ खराब निकला है। कई बार बदलने के लिए बोला तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में मजबूर होकर खराब गेहूं की बोवनी करना पड़ रही है। इससे हमारी उपज पर असर पड़ेगा।

- प्रीतम सिंह अहिरवार, किसान, ग्राम भैंरोपुरा

कृषि विभाग द्वारा किसानों को गेहूं के बीज की किस्म 8737 अनमोल उपलब्ध कराई गई है।यह खराब गुणवत्ता का है। जबकि विभाग का दावा है कि यह सभी जगह से सत्यापित बीज है। अब तक भोपाल सहित 10 जिलों से बीज खराब होने की जानकारी मिली है।

- अखिलेश मीणा, किसान नेता, भारतीय किसान संघ

बीज निगम से भेजी गई अनमोल 8737 किस्म के गेहूं का बीज खराब निकलने की शिकायतें मिली हैं। कृषि विस्तार अधिकारियों को किसान से खराब बीज लेकर अच्छा बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

- सुमन प्रसाद, उप संचालक, कृषि विभाग

शिवराज ने अफसरों को दिए सख्त कार्रवाई का निर्देश

नकली खाद-बीज बेचने वालों को छोड़ना मत...

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि देश के किसानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता की खाद, बीज और कीटनाशक मिलना तय किया जाना चाहिए। शिवराज ने अपने मंत्रालय की विभागवार समीक्षा के दौरान इस संबंध में अफसरों को किसानों की व्यापक भलाई के लिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चौहान ने कहा कि कई राज्यों में ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई प्रभावी नहीं होने से छूट जाते हैं। इस बारे में वे स्वयं शीघ्र ही राज्य सरकारों से बात करेंगे, ताकि राज्यों के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई निरंतर की जाती रहे, जो कोई भी दोषी पाया जाए, उन्हें कड़ी सजा मिल सके, जिससे कि ऐसे घृणित कृत्य रुक सके। शिवराज ने कहा कि राज्यों में प्रवास के दौरान किसान हमसे शिकायत करते हैं कि उन्हें कई बार घटिया क्वालिटी के ये आदान मिलते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है।

प्रभावी कार्रवाई करें

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में सख्त लहजे में कहा कि एक जागरुक जनप्रतिनिधि के तौर पर हम किसानों की इन शिकायतों को लेकर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया कि नकली या घटिया किस्मों के कीटनाशक, खाद एवं उर्वरकों पर प्रभावी नियंत्रण के ठोस उपाय किए जाने चाहिए। आगामी फसल सीजन के मद्देनजर भी किसानों को इस संबंध में राहत मिलना चाहिए, इसके लिए वे शीघ्र ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इस बारे में राज्यों के स्तर पर ही प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है।

दोषियों का नहीं मिलती सजा

समीक्षा के दौरान शिवराज ने पूछा कि ऐसे नकली आदान बनाने-बेचने वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है। इस दौरान यह बात सामने आई कि कई राज्यों के स्तर पर जांच-पड़ताल और अभियोजन के स्तर पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अधिकांश दोषी लोग बरी हो जाते हैं या उन्हें बहुत कम दंड मिलता है।

संयुक्त अभियान चलाया जाए

राज्यों में प्रभावी कार्रवाई किसी भी सूरत में की जाना चाहिए। घटिया खाद, बीज और कीटनाशक के मामले में बड़े विक्रेताओं और निर्माताओं पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाना चाहिए और मौजूदा कानूनों, नियम-प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। चौहान ने कहा कि कीटनाशकों, खाद और उर्वरकों के अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से एक अभियान चलाना चाहिए।

29 एकड़ 45 डिस्मिल शासकीय भूमि पर था पारदियों का कब्जा

भैरूंदा कृषि उपज मंडी का रास्ता साफ

सीहोर। जागत गांव हमार

सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के ग्राम राला के पास नवीन कृषि उपज मंडी को लेकर अब रास्ता साफ हो गया है। बुधनी उपचुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के हटते ही प्रशासन एक्शन मोड में आया और अतिक्रमणकारियों से जमीन को मुक्त कराया। दरअसल, कृषि उपज मंडी भैरूंदा को ग्राम राला के पास पारदीपुरा टप्पर पर शिफ्ट किया जाना है, लेकिन यहां पर लंबे समय से पारदियों का कब्जा है। यहां पर करीब 29 एकड़ शासकीय भूमि पर पारदियों ने कच्चे आवास बनाकर कब्जा कर रखा था। कई बार प्रशासन ने यहां से कब्जा हटाने की पहल की, लेकिन विरोध के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा। इस बार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की थीं। भैरूंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी दीपक कपूर, तहसीलदार सौरभ शर्मा, नायब तहसीलदार संदीप गौर, थाना प्रभारी घनश्याम दांगी, कृषि उपज मंडी समिति सचिव बिल्यम जार्ज, सह प्रभारी उमेद धुर्वे, गोपालपुर थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह गौर, इछावर थाना प्रभारी बृजेश कुमार सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एवं शासकीय जमीन पर बने पारदियों के कच्चे टप्परों पर जेसीबी मशीन चलाई। हालांकि इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन प्रशासन की पुख्ता तैयारियों के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। करीब छह घंटे की कार्रवाई के बाद जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

पुख्ता तैयारियों के साथ पहुंचा जिला और पुलिस प्रशासन

भैरूंदा की नवीन कृषि उपज मंडी बनने वाली भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। इस वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। भैरूंदा कृषि उपज मंडी में जगह कम होने के कारण जहां आए दिन किसानों को परेशानियां होती थीं तो वहीं मुख्य मार्ग पर भी जाम जैसे हालात पैदा हो जाते थे, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। राला के पास बने पारदियों के टप्परों पर अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम, एसडीओपी भारी पुलिस बल लेकर पहुंचे और कब्जाधारियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि इस भूमि पर मंडी का निर्माण जल्द ही शुरू होगा, जिससे किसानों की समस्याएं हल हो सकेंगी। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय क्षेत्र में हलचल मच गई। वहीं स्थानीय किसानों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है और मंडी निर्माण जल्द होने की उम्मीद जताई है।

टेंडर प्रक्रिया पहले ही हुई, अब शुरू होगा निर्माण

प्रशासन के मुताबिक इस भूमि पर मंडी निर्माण का टेंडर पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन कब्जाधारियों के विरोध के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में सीहोर और इछावर से पुलिस बल बुलाया गया और क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संबंधित भूमि कृषि उपज मंडी के लिए आवंटित है और अतिक्रमण के कारण मंडी निर्माण कार्य बार-बार बाधित हो रहा था। कई बार कब्जा हटाकर निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन हर बार अवैध कब्जाधारियों ने काम रुकवा दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया, जिन्हें पुलिस बल की निगरानी में रखा गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस भूमि पर मंडी निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने में हो रही समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

कार्रवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी

प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरती, ताकि कोई अप्रिय स्थिति सामने आने पर उससे निपटा जा सके। प्रशासन द्वारा पूरी कार्रवाई के दौरान डोन कैमरों से नजर रखी गई तो वहीं वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। सीहोर सहित इछावर, गोपालपुर से भी पुलिस बल बुलाया गया। कई थानों के थाना प्रभारियों को भी यहां पर तैनात किया गया। हालांकि पुलिस की पुख्ता तैयारियों के कारण ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हो सकी।

शादी में गए थे, लेकिन सूचना मिलते ही लौटे

बताया जा रहा है कि जिस जमीन को खाली कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन पहुंचा उसके कब्जाधारी कहीं बाहर शादी में गए हुए थे। कुछ लोग थे, जिन्होंने प्रशासन के सामने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने पहुंचाकर वहां पर बैठा दिया। इसके बाद जब शादी में गए लोगों को सूचना मिली तो वे वापस लौट आए, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में था। जैसे ही वे लोग अपनी गाड़ियों से आए उन्हें भी पुलिस ने घेराबंदी करके गाड़ियों में बैठाकर थाने में पहुंचा दिया। इस दौरान कार्रवाई लगातार जारी रही। इस संबंध में भैरूंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना है कि राला के पारदीपुरा टप्पर पर 29 एकड़ 40 डिस्मिल जमीन पर कृषि उपज मंडी का निर्माण कार्य किया जाना है, जिस पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा था। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य करने आए लोगों को इन कब्जाधारियों द्वारा पत्थरबाजी कर धारदार हथियारों से डराया जाता था। कई बार इन्हें समझाइश दी गई, लेकिन नहीं माने। अब राजस्व अमले सहित पुलिस प्रशासन द्वारा कब्जा हटाकर 29 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। अब जल्द ही मंडी का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इस संबंध में एसडीओपी, भैरूंदा दीपक कपूर का कहना है किकृषि उपज मंडी को लेकर काफी समय से मांग की जा रही थी, लेकिन यहां पर कब्जाधारियों द्वारा निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा था। कई बार इन्हें समझाया गया, लेकिन समझाइश काम नहीं आई। अब पुलिस बल के साथ शांतिपूर्वक कब्जा हटाया गया है।

एक करोड़ किसानों को जोड़ने का टारगेट

नेचुरल फॉर्मिंग मिशन में 2025-26 तक 2481 करोड़ होंगे खर्च

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने धरती की सेहत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग की शुरुआत का ऐलान किया है। इस पर 2,481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत एक करोड़ किसानों को शामिल करने का टारगेट सेट किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में नेचुरल फॉर्मिंग का पहला एक्सपेरिमेंट 2019-20 में हुआ था। इसका अच्छा रिजल्ट आया। कई लोगों ने इसको बहुत उत्साह के साथ अपनाया। इसके बाद 2022-23 में एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके तहत गंगा के किनारे दोनों तरफ 5-5 किमी का कॉरिडोर लेकर नेचुरल फॉर्मिंग और केहमकल फ्री फॉर्मिंग पर काम किया गया। इन दोनों एक्सपेरिमेंट का बहुत अच्छा परिणाम आया। इसके तहत देश भर में 9.6 लाख हेक्टेयर कवर किया गया। इस सफलता के बाद अब सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है। ताकि धरती की सेहत अच्छी रहे और लोगों को खानेपीने की चीजें केमिकल फ्री मिलें। इस बात बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग या पंचायतें नेचुरल फॉर्मिंग करने के इच्छुक हैं उनको आगे लाएं। ऐसे लोगों को पूरी मदद दी जाएगी।

मिशन का मकसद

- प्रकृति आधारित सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देना। बाहर से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता कम करना। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और किसानों की इनपुट लागत को कम करना।
- इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर-एनिमल हस्बैंडरी मॉडल को लोकप्रिय बनाना। सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े संस्थानों, कवीके, कृषि विवि आदि की एग्रो-इकोलॉजिक रिसर्च और ज्ञान-आधारित विस्तार क्षमता को मजबूत करना।
- प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के अनुभव और वैज्ञानिक विशेषज्ञता को एक साथ लाना।
- प्राकृतिक रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पादों के लिए मानक और आसान सर्टिफिकेशन।
- प्राकृतिक रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पादों के लिए राष्ट्रीय ब्रांड बनाना,उसे बढ़ावा देना।

राज्यों का भी हिस्सा होगा

नेचुरल फॉर्मिंग मिशन में 2025-26 तक कुल 2481 करोड़ खर्च होंगे। इसमें 1584 करोड़ भारत सरकार और 897 करोड़ राज्यों का हिस्सा होगा। अगले दो वर्षों में, एनएमएनएफ को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा। किसानों को इस खेती में उपयोग करने के लिए तैयार इनपुट की आसान उपलब्धता करवाने की जरूरत को देखते हुए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एनएमएनएफ के तहत, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों पर लगभग 2000 मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे।

सरकार ने खरीद टारगेट 3.50 लाख मीट्रिक टन तय किया

मध्य प्रदेश में ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों से उपज खरीद के लिए 1400 से अधिक केंद्रों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तर पर पेमेंट भुगतान तक किसानों को होने वाली किसी भी तकनीकी समस्या को हल करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर तकनीकी सेल का गठन किया गया है। किसानों को उपज बिक्री का भुगतान सीधे उनके खाते में 48 घंटे के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 22 नवंबर से ज्वार और बाजरा किसानों से उपज खरीद शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद 22 नवंबर से सरकारी खरीद की जा रही है। किसान अपनी फसल को 20 दिसंबर 2024 तक बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि उपज की खरीद पूरे सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक होगी। शनिवार और रविवार को फसल खरीद बंद रहेगी।

सरकार ने मोटे अनाज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर शुरू कर दी है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को एमएसपी पर उपज खरीद की मंजूरी दी है। ज्वार मालदंडी किस्म के लिए एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। जबकि, ज्वार की हाइब्रिड किस्म के उपज के लिए सरकार ने 3,371 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। इसी तरह बाजरा के लिए 2,625 रुपए क्विंटल एमएसपी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी पर उपज खरीद का पैसा भुगतान कर रही है।

16 हजार किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

मध्य प्रदेश सरकार ने ज्वार और बाजरा का कुल खरीद टारगेट 3.50 लाख मीट्रिक टन तय किया है। इसमें से बाजरा खरीद का टारगेट 3 लाख मीट्रिक टन है और ज्वार खरीद का टारगेट 50 हजार मीट्रिक टन तय किया गया है। दोनों फसलों की बिक्री के लिए कुल 16 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। बाजरा की बिक्री के लिए 9854 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ज्वार की बिक्री के लिए 5933 किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है।

कंट्रोल रूम और टेलीफोन नंबर

राज्य कृषि विभाग ने कहा कि किसानों से फसल खरीद के दौरान समस्या दूर करने और मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इसके लिए टेलीफोन नंबर 0755-2551471 जारी किया गया है। इस नंबर पर किसान सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक कॉल करके अपनी समस्याओं या दिक्कत को बताकर हल हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और खरीद में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिलावार एक तकनीकी सेल का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति खरीद संबंधी सभी विवादों का निपटान, खरीद उपज की क्वालिटी की निगरानी करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- दो लाख गांवों में मल्टीपरपज पैक्स बन रही केंद्र सरकार

सहकार से आंदोलन आंदोलन से क्रांति...

भारत के अनुभवों के माध्यम से वैश्विक सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी के उपकरण और नई भावना मिलेगी

किसानों के लिए गोदाम बना रहीं आठ लाख सहकारी समितियां

भोपाल। जागत गांव हमार

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज 8 लाख सहकारी समितियां हैं, जो किसानों को लोकल सॉल्यूशन दे रही हैं। देश के 98 फीसदी ग्रामीण हिस्से को सहकारी समितियां कवर करती हैं। इनको मल्टीपरपज बनाकर किसानों, मजदूरों के काम में लाया जा रहा है। दो लाख ऐसे गांवों में मल्टीपरपज सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। जहां कोई समिति नहीं है। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस (आईसीए) की ओर से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी कहा कि मैं भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं और भारत को जोड़ने वाले युवाओं की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में हम सहकारिता आंदोलन का विस्तार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से हमें भारत की भावी सहकारिता यात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही, भारत के अनुभवों के माध्यम से वैश्विक सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी के उपकरण और नई भावना मिलेगी।

सहकारी समितियां स्टोरेज सुविधा बढ़ा रहीं- पीएम मोदी ने कहा कि हम कह सकते हैं कि भारत में सहकारिता ने सहकार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। आज हम भारत सरकार और सहकार की शक्ति को एकसाथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। भारत में आज 8 लाख सहकारी समितियां है। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। आज भारत सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर काम कर रहा है। इस योजना को हमारी सहकारिता समितियां चला रही हैं। इस योजना के तहत हम पूरे देश में गोदाम बना रहे हैं, जहां किसान अपनी उपज रख सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा सीमांत किसानों को होगा।

गांवों में पैक्स मल्टीपरपज काम कर रहीं

पीएम ने आगे कहा कि ये सहकारी समितियां किसानों को लोकल सॉल्यूशन देने वाले सेंटर चला रही हैं। डीजल, पेट्रोल आउटलेट चलाए जा रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सोलर पैनल लगाने का काम कर रही हैं। यह समितियां कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए डिजिटल सेवाएं दे रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। दो लाख ऐसे गांवों में मल्टीपरपज सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। जहां कोई समिति नहीं है।

98 फीसदी हिस्से को पैक्स कवर कर रहीं

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल देखता है, इसलिए हमने बीते 10 वर्षों में कोऑपरेटिव से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। हमारा प्रयास है कि कोऑपरेटिव समितियों को मल्टीपरपज बनाया जाए। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। ग्रामीण भारत के करीब 98 फीसदी हिस्से को कोऑपरेटिव कवर करती हैं। करीब 30 करोड़ लोग यानी भारत में हर पांच में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। आज भारत में लगभग 2 लाख हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा उतनी तेजी से ग्रो करेगा।

कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का ऐलान

तीन साल बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पैक्स न हो

इधर, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन साल के बाद देश का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसायटी यानी पैक्स नहीं होगा। दो लाख नए पैक्स के माध्यम से ऐसा संभव होगा। पैक्स को आधुनिक बनाने, टेक्नोलॉजी से लैस करने और आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए भी कई फैसले हुए हैं। तीन नई सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं जिससे भारत का किसान न केवल अपने देश बल्कि दुनिया भर के बाजार तक अपनी पहुंच बना सकता है। इन कंपनियों में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड शामिल हैं। शाह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। यह फैसला दुनिया के करोड़ों किसानों और महिलाओं के लिए आशीर्वाद के रूप में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। आईसीए का अंतराष्ट्रीय सम्मेलन और अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा का भारत की जमीन से होना बेहद महत्वपूर्ण है। तीन साल पहले भारत में सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की गई थी। इसके बाद कई काम किए गए हैं।

इफको, कृभको और अमूल की तारीफ

शाह ने कहा कि इफको, कृभको और अमूल ने सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया के सामने उदाहरण पेश करने का काम किया है। उसी तरह भारत में बनाई गई तीनों नई सहकारी कंपनियां दुनिया के सहकारी क्षेत्र के लोगों का मार्गदर्शन करेंगी। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इससे जुड़े पूरे कानूनी ढांचे का पुनर्गठन हुआ है। साथ ही श्वेत क्रांति पार्ट-2 की शुरुआत भी हुई है, जिसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

आएगी सहकारिता नीति

आने वाले कुछ ही दिनों में हम सहकारिता का विवि भी बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन का विकास आसानी से होगा। इसी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में ही हम भारत की सहकारिता नीति भी लाएंगे। इसके साथ ही हम सहकारी क्षेत्र में लंबा रास्ता तय करना सुनिश्चित करेंगे। हम हर गांव और हर किसान को सहकारिता से जोड़ना चाहते हैं। हम इसके लिए नए-नए क्षेत्रो को भी तलाश रहे हैं। गांव, किसान, महिला और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता आंदोलन ने कई सारे रास्ते खोले हैं।

जानिए कैसे करें शुद्ध डीएपी और एनपीके की पहचान

डीएपी तथा एनपीके में कौन है बेहतर

भोपाल। जागत गांव हमार

डीएपी तथा एनपीके में बेहतर कौन है? भारतीय कृषि में उर्वरक (खाद) का एक मत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी तरह की फसल हो उसमें खाद का प्रयोग जरूर करते हैं। किसान भाई ज्यादा तर बुवाई के समय डीएपी तथा एनपीके खाद का ही प्रयोग करते हैं बिना यह जाने की इनके प्रयोग से उन्हें क्या फायदा या नुकसान है। अक्सर किसानों के पास दोनों खादों को लेकर एक ही सवाल रहता है की दोनों में से बेहतर कौन है तथा किस फसल के लिए कौन सी खाद ज्यादा उपयोगी है।

डीएपी: डीएपी का पूरा डाईअमोनियम फॉस्फेट होता है। इसमें 18प्रतिशत नाईट्रोजन तथा 46प्रतिशत फास्फोरस होता है। इस 18प्रतिशत नाईट्रोजन में से 15.5प्रतिशत अमोनियम नाइट्रेट होता है एवं 46प्रतिशत फास्फोरस में से 39.5प्रतिशत फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है एवं शेष फास्फोरस मिट्टी में ही घुलता है।

शुद्ध डीएपी और एनपीके की पहचान

डीएपी सख्त, दानेदार, भूरा, काला, बादामी रंग नाखूनों से आसानी से नहीं छूटता। डीएपी के कुछ दानों को लेकर तम्बाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मलने पर तीक्ष्ण गन्ध निकलती है, जिसे सूंघना असह्य हो जाता है। तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर दाने फूल जाते हैं।

एनपीके: एनपीके उर्वरक तीन तरह के अनुपात में आते हैं, जोकि पैकेट पर लिखा रहता है जैसे 18:18:18, 19:19:19 तथा 12:32:16: के अनुपात में लिखा रहता है। इसमें पहला अंक नाईट्रोजन दूसरा अंक फास्फोरस तथा तीसरा अंक पोटेसियम होता है। ज्यादातर किसान 12:32:16 का ही प्रयोग करते हैं। इसमें 12 नाईट्रोजन, 32 फास्फोरस तथा 16 पोटैशियम होता है 7 अभी कुछ समय से जिंक कोटेड रहने पर 0.5 जिंक की मात्रा रहती है।

शुद्ध यूरिया अथवा एनपीके उर्वरक की पहचान

किसान भाई नीचे दिए गए गुणों से कर सकते हैं। सफेद चमकदार, लगभग समान आकार के गोल दाने। पानी में पूर्णतया घुल जाना तथा घोल छूने पर शीतल अनुभूति। गर्म तवे पर रखने से पिघल जाता है और आंच तेज करने पर कोई अवशेष नही बचता।

उपयोग:- दोनों खाद दानेदार रहती है। इसलिए दोनों खाद को बीज की बुवाई के समय प्रयोग करें। एनपीके (12:32:16) का प्रयोग दानेदार फसल के लिए करें जैसे धान, मुंग, उड़द, गेंहू इत्यादी। इसमें 16प्रतिशत पोटेशियम रहता है, जिससे फसल के दानों में चमक तथा वजन बढ़ता है।

डीएपी:- डीएपी में पोटैशियम नहीं होता है। जिस कारण दानेदार फसलों के लिये उतना उपयुक्त नहीं है, जितना की एनपीके होता है। इसलिए आप इसका प्रयोग फूल वाली फसल सब्जियों के लिए कर सकते हैं। एनपीके घुलनशील है जबकि डीएपी नहीं है। इसलिए डीएपी कुछ समय के बाद मिटटी में मिलने के बाद पौधों में असर दिखता है। एनपीके हल्की जमीन के लिए उपयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है। जबकि डीएपी भारी जमीन के लिए उपयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर एक ही तरह की जमीन है तो फिर एनपीके उपयोग करना ज्यादा बेहतर है। अगर डीएपी के साथ स्ट्र्फ्क (60प्रतिशत वाला) मिलायें तो अच्छा रिजल्ट देता है।

निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों मरीजों को मिला ईलाज

भोपाल। जागत गांव हमार

राजधानी के जाने-माने वैद्य बीएस राजैरा और गीता बिसेन के देखरेख में जेके रोड स्थित आल्टोस कंपनी के परिसर में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास के सैकड़ों लोगों ने अपना परीक्षण करवाकर निःशुल्क ईलाज करवाया।

वैद्य बीएस राजैरा ने बताया कि शिविर में दमा, स्वांस, शुगर और अन्य कई रोगों से पीड़ित लोग आए, जिनका विधिवत परीक्षण कर निःशुल्क ईलाज किया गया और उन्हें ठंड के मौसम में अपना बचाव करने संबंधित सावधानी रखने की उचित सलाह भी दी गई। आल्टोस कंपनी के डायरेक्टर जेपी ठाकरे ने बस राजोरा और गीता विषय का सम्मान किया।

वैद्य राजौरा और गीता बिसेन का सम्मान

शिविर के उपरांत आल्टोस कंपनी के डायरेक्टर जेपी ठाकरे ने वैद्य बीएस राजौरा और गीता बिसेन का शाल-श्रीफल देकर सम्मान किया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में जेपी ठाकरे, तारम और भवदीय तथा श्रीप्रसाद अहिरवार का सहयोग मिला।

प्रदेश के विकास में उद्यानिकी का महत्वपूर्ण योगदान

नारायण सिंह कुशवाह
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंकरण तथा सामाजिक न्याय मंत्री, मप्र

देश और प्रदेश की उन्नति सर्वोपरि है। इसके लिए किसानों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त करना आवश्यक है, जिससे किसान संपन्न हो सकें और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकें। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक विकास की गति किसानों के उत्थान से ही संभव हो सकती है। इसके लिए प्रदेश के विकास में उद्यानिकी भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इसके लिये नवाचार और तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं।

देश के 10प्रतिशत क्षेत्रफल वाले राज्य मध्यप्रदेश में देश की लगभग 7प्रतिशत आबादी निवास करती है। यहां 11 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। राज्य की कृषि उपज में विविधता मुख्यत: नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार परिणाम देने वाली नीतियों के माध्यम से उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में नवाचार और प्रगति के नए अध्याय लिख रही है। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उद्यानिकी फसलें किसानों की आय को आसानी से दोगुना करने में सहायक होती हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्र-संस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को उद्यानिकी फसलों की खेती और खाद्य प्र-संस्करण के नए तरीकों से अवगत कराया जा रहा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश संतरा, धनिया मसाले तथा औषधीय एवं सुगंधीय पौधे उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त प्रदेश टमाटर, लहसुन, हरी मटर, अमरूद, फूल गोभी, मिर्च एवं प्याज उत्पादन में दूसरे तथा नीबू वर्गीय फल, लाल मिर्च, बंद गोभी एवं फूल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है ।

राज्य में उद्यानिकी का रकबा बढ़कर लगभग 27 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में उद्यानिकी के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है। इस कारण रकबा 2019-20 में 21.75 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 26.51 लाख हेक्टेयर हो गया है। लगभग 23.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्पादन भी लगभग 27 फीसदी बढ़ा है। वर्ष 2019-20 में जो उत्पादन 317.36 लाख मी. टन था, जो बढ़कर अब 404.24 लाख मी. टन हो गया है।

किसानों को उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। सरकार से अनुदान लेकर किसान फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ स्थापित कर सकते हैं। साथ ही अनुदान के आधार पर किसान छोटे, मध्यम और बड़े कोल्ड स्टोर भी स्थापित कर सकते हैं। खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अपने समृद्ध कृषि संसाधन और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का उपयोग कर, 8.3प्रतिशत की औसत /वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है. उद्यानिकी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण के लिए 21530.26 लाख रुपए की अनुदान सहायता से 183 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर 8.05 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित की गई है। वहीं प्याज भंडारण के लिए 23667.71 लाख रुपए का अनुदान देकर 66500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता किसानों के खेतों पर निर्मित की गई है।

प्रदेश में बागवानी को शिखर पर ले जाने के प्रयासों में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पी.पी.एम.सी), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाय.) के तहत वर्ष 2024-25 में 528 करोड़ 91 लाख रुपए की कार्ययोजना मंजूर की गई है। राज्य में उद्यानिकी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 16 विभिन्न बागवानी उत्पादों को जी.आई. टैग के लिए पंजीयन कराया गया है। सूक्ष्म सिंचाई द्वारा राज्य में 14 हजार 900 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 12 हजार 790 हितग्राहियों को 114 करोड़ 76 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इजराइल तकनीक के समन्वय से प्रदेश में मुरैना में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी के लिए, छिंदवाड़ा में नींबूवर्गीय फसलों के लिए तथा हरदा में निर्यात करने लायक आम एवं सब्जी सेन्टर की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 14 करोड़ 74 लाख की योजना का अनुमोदन किया गया है।

प्रदेश सरकार की नई पहल ई-नर्सरी पोर्टल से घर, गार्डन या खेतों में उत्तम गुणवत्ता के पौधे लगाने के लिये, अच्छे और स्वस्थ पौध के लिये अब नर्सरी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उद्यानिकी विभाग द्वारा ई-नर्सरी पोर्टल पर 300 से अधिक नसज़रियों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गई है। इससे पौधों का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है।

24 बागवानी उत्पाद जिनकी खेती आमतौर पर राज्य भर में की जाती है, जिनमें कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/नींबू, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लहसुन अदरक, धनिया, सरसों, गन्ना, आंवला और हल्दी शामिल हैं। छिंदवाड़ा, आगर-मालवा, शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर, बैतूल और सीहोर जैसे जिले संतरे के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं जो संतरे के प्र-संस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए आदर्श हैं। इसी तरह बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले जो आम की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, वहां कई आम आधारित खाद्य प्र-संस्करण उद्योग हैं जो स्थापित होने के विभिन्न चरणों में हैं।

मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग को उत्कृष्ट कार्याें के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार एवं प्रशंसा-पत्र भी प्राप्त हुए हैं। जुलाई 2024 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एग्री एवं हार्टी एक्सपो-2024 में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग मध्यप्रदेश को सर्वोत्तम बागवानी पद्धतियों और सब्जियों एवं ताजे फलों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। एमपीएफएसटीएस पोर्टल के संचालन के लिए वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय कृषि तथा उद्यानिकी एक्सपो-2023 में 'एक्सीलेंस अवॉर्ड, नेशनल ओडीओपी अवॉर्ड सेरेमनी-2023 में प्रदेश के बुरहानपुर जिले को केला उत्पादन तथा प्र-संस्करण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं वर्ष 2022-23 में 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत बेहतर क्रियान्वयन के लिए उद्यानिकी विभाग को स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रदेश में फसल क्षेत्र का विस्तार और उत्पादन में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौधों और उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। उत्पादन के पहले और बाद में प्रबंधन तकनीकों के जरिए फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बेहतर बनाना, फसल के उचित मूल्य के लिए खाद्य प्र-संस्करण और विपणन के साधनों में सुधार, अत्याधुनिक कृषि तकनीकों के जरिए संरक्षित खेती को बढ़ावा देना, किसानों को तकनीकी और वित्तीय समर्थन एवं कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए समन्वय करना आदि चहुँमुखी प्रयासों से उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को अधिकतम लाभ पहुँचाने और आमदनी दोगुनी करने का कम कर रही है।

पशुओं में रक्त मूत्रमेह तथा रक्त हीमोग्लोबिनमेह रोगों का सरल विभेदात्मक निदान

» डॉ. शुभ्रदल नाथ
» डॉ. संजू मंडल
» डॉ. अनिल गट्टानी
» डॉ. अनिल गट्टानी
» डॉ. अमित कुमार
» डॉ. आफरीन खान
- पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, मप्र

गोणिका वृक्कशोथ तथा मूत्राशय शोथ: इसे पायलो-नेफ्राइटिस भी कहा जाता है, जो कि मूत्र संस्थान के निचले भाग के आरोही संक्रमणों रक्तमार्ग से व्युत्पन्न इम्बोलिक वृक्कशोथ सीडोमोनास एरूजिनोसा तथा कोरिनी बैकटीरियम रीनेल के कारण उत्पन्न होता है। उदर पीड़ा, बढ़े हुये गुर्दे तथा रक्त मूत्र मेह रोग की पहचान है।

ब्यांतोपरांत मूत्र हीमोग्लोबिन मेह: यह रोग ब्यांत के 5-6 सप्ताह पश्चात् अत्याधिक दुधारू गायों में होता है यह एक तीव्र प्रकार का रोग है जिसमें न तो दुग्ध में कोई परिवतज़्न होता है और न ही ज्वर आता है। इस में अत्याधिक मूत्र हीमोग्लोबिनमेह देखा जाता है तथा रोगी गौपशु की कुछ ही घंटो में मृत्यु हो जाती है। रोग का कारण फास्फेट हीनता है।

दण्डाणु मूत्र हीमोग्लोबिन मेह: कुछ विशिष्ट स्थानों में चारागाहों में रूग्णता आघटित होती है। रोगी गौ-पशु को तीव्र ज्वर एवं पीड़ा होती है। वह 2-4 दिनों में मर जाता है। मूत्र हीमोग्लोबिन मेह इस मेह रोग का लक्षण है। रक्त परीक्षण करने पर श्वेत कोशिकाओं की संख्या में कमी अथवा वृद्धि मिलती है।

बेबेसियता: यह स्थानिक क्षेत्रों में चीचड़ों द्वारा संचारित युवा गौ-पशुओं का प्रोटोजोआ जनित रोग है। इस रोग में तीव्र ज्वर, पीलिया, गर्भपात (गायों में) उत्पन्न होता है। रोग काल 2-3 सप्ताह का है। मूत्र हीमोग्लोबिन मेह रोग का नैदानिक लक्षण है रोग निदान रक्त आलेप के परीक्षण, संचरण तथा अन्य प्रयोगशालीय परीक्षणों द्वारा किये जाते हैं।

ताम्र विषाक्तता: यह लम्बे समय तक ताम्र या कापर युक्त आहार अथवा औषधियों देने से उत्पन्न होती है। रोगी गौ-पशुओं को तीव्र पीलिया उत्पन्न होती है। रोग ग्रस्त पशु को ज्वर नहीं होता है किंतु उस को मूत्र हीमोग्लोबिन मेह होता है। रक्त, यकृत तथा गोबर में ताम्र की विषैली मात्रायें पायी जाती हैं।

शीतल जल रक्तसंलयी अरक्तता: सीमित प्यासे रहने के पश्चात् अत्याधिक मात्रा में ठंडा पानी पीने से बछड़ो में यह रोग उत्पन्न होता है। जल ग्रहण करने के एक घंटे के अंदर रोग उत्पन्न होता है इस रोग में ज्वर नहीं होता है। बछड़ों को मूत्र हीमोग्लोबिन मेह होता है तथा उनकी कुछ घंटों पश्चात् मृत्यु हो जाती है। रोगी बछड़ों में रक्त-संलयी अरक्तता का निदान होता है।

रेप और केल विषाक्तता: फाल मौसम में चारे के लिये उगायी रेप की फसल पर सभी आयु के भी पशुओं में यह विषाक्तता उत्पन्न होती है। विषाक्तता ग्रस्त पशुओं में अति तीव्र रक्त संलयी अरक्तता होती है। रोगी पशु को ज्वर नहीं उत्पन्न होता है तथा वह रोग आरंभ होने के कुछ घंटों पश्चात कालग्रस्त हो जाता है। मूत्र हीमोग्लोबिन मेह रोग का लक्षण है।

औषध व्युत्पन्न मूत्र हीमोग्लोबिन मेह: अंत: शिरा विधि से कुछ औषधियां देने से यह रूग्णता उत्पन्न होती है। इस में यद्यपि रक्त संलयी अरक्तता नहीं उत्पन्न होती है किंतु हल्की मूत्र हीमोग्लोबिन मेह देखी जाती है।

स्थानिक गौपशु रक्त मूत्र मेह: यह गौपशुओं का एक चिरकारी रोग है जो कि मूत्राशय के प्रफलनीय शोथ और/अथवा विविध प्रकार की रसोलियों (सुदम/दुर्दम कैंसर) के कारण स्थानीय रक्ताधिक्य, चक्रीय अथवा निरंतर होने वाले रक्तस्राव के फलस्वरूप रक्त मूत्रमेह (लहुसुतिया, लहुगौतया खून गोतने) के कारण अरक्तता एवं मृत्यु द्वारा पहचाना जाता है। रोग के कारण कम मात्रा में लम्बे समय तक ब्रेकनफर्न (टेरिडियम एक्यूलाईनम) का अधिग्रहण है।

शिह त्जु डॉग की देखभाल, स्वास्थ्य पोषण और उचित प्रबंधन के बेहतरीन उपाय

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. आर.के बघेरवाल
» डॉ. एच.के मेहता
» डॉ. अरुण मौर्य
» डॉ. निधि सिंह चौधरी
» डॉ. मुकेश शाक्य
-पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय महू, इंदौर, मप्र

शिह त्जु एक प्यारी और लोकप्रिय नस्ल है, जिसे उसके रेशमी लंबे बाल, शांत स्वभाव और दोस्ताना व्यवहार के लिए जाना जाता है। यह नस्ल विशेष रूप से परिवारों के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसकी देखभाल में विशेष ध्यान देना जरूरी है।

शिह त्जु के शारीरिक और व्यवहारिक लक्षण: **शारीरिक लक्षण**- शिह त्जु का वजन आमतौर पर 4-8 किलोग्राम होता है और ऊंचाई 8-11 इंच तक होती है। इनकी आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण और चोट का खतरा रहता है। **व्यवहारिक विशेषताएं:** ये कुत्ते मिलनसार, खुशमिजाज और बच्चों के साथ दोस्ताना होते हैं। हालांकि, ये आलसी हो सकते हैं, जिससे इनका वजन बढ़ सकता है।

ग्रूमिंग और सफाई: शिह त्जु का कोट उनकी पहचान है, लेकिन यह उनकी देखभाल का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भी है। **नियमित ब्रशिंग:** शिह त्जु के बाल उलझने और गंदगी जमा होने के कारण संक्रमण का खतरा रहता है। रोजाना ब्रशिंग करें। डॉग-कंडीशनर का उपयोग करें। **स्नान:** हर 2-3 सप्ताह में इन्हें गुनगुने पानी से नहलाएं। शिह त्जु की त्वचा संवेदनशील होती है, इसलिए, हाइपोएलर्जेनिक शैम्पू का उपयोग करें। आंखों और कानों की सफाई -उनकी आंखों में गंदगी या आंसुओं के दाग को साफकरें। कानों की सफाई के लिए पशु चिकित्सक द्वारा सुझाए गए ईयर क्लीनर का उपयोग करें। **नाखूनों की देखभाल:** उनके नाखूनों को हर महीने ट्रिम करें, ताकि वे टूटे या चोटिल न हों।

पोषण आवश्यकताएं: इनके आहार में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का सही संतुलन होना चाहिए। मांस, सब्जियां और अनाज उनके लिए उपयुक्त हैं। **मील टाइमिंग:** इन्हें दिन में 2-3 बार खाना दें, ताकि उनके पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव न पड़े। **वजन प्रबंधन:** इनका वजन जल्दी बढ़ सकता है। कैलोरी की निगरानी करें और उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचें।

व्यायाम और शारीरिक सक्रियता: हालांकि शिह त्जु छोटे और घर के अंदर रहने वाले कुत्ते हैं, लेकिन उन्हें नियमित व्यायाम की जरूरत होती है। इन्हें दिन में कम से कम 20-30 मिनट टहलाएं। व्यायाम से उनका वजन नियंत्रित रहता है और उनकी ऊर्जा का उपयोग होता है।

स्वास्थ्य समस्याएं और रोकथाम: शिह त्जु को उनकी शारीरिक संरचना और नस्लीय विशेषताओं के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। **आंखों की समस्याएं:** शिह त्जु की बड़ी आंखें संक्रमण और चोटों के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। नियमित रूप से आंखों की जांच करें और गंदगी साफ करें। **सांस की समस्याएं:** छोटे थूथन के कारण उन्हें गर्मी में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गर्मी में उन्हें ठंडी जगह पर रखें और अत्यधिक व्यायाम से बचें। **हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं:** उम्र बढ़ने के साथ शिह त्जु में आर्थराइटिस या हिप डिस्प्लेसिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं उनके आहार में कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल करें। **टीकाकरण और परजीवी नियंत्रण:** नियमित रूप से उनके टीकाकरण और डीवॉर्मिंग का ध्यान रखें।

मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण: शिह त्जु का मानसिक स्वास्थ्य उनकी खुशी और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। **प्रशिक्षण:** सकारात्मक प्रशिक्षण तकनीकों का उपयोग करें। इनाम आधारित प्रशिक्षण उन्हें जल्दी सीखने में मदद करता है। **मानसिक व्यायाम:** इंटरएक्टिव खिलौने कुत्ते को मानसिक रूप से सक्रिय रखने के लिए बेहतरीन हैं।

शिह त्जु एक विशेष नस्ल है, जिसकी देखभाल में नियमितता और ध्यान की आवश्यकता होती है। सही आहार, ग्रूमिंग, व्यायाम और स्वास्थ्य प्रबंधन से आप न केवल उनके जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक खुश और सक्रिय रख सकते हैं।

कम समय में दो गुना होगा फायदा

किसानों के लिए फयदेमंद हो सकती है आलू-मक्का की सह-फसली खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान मिश्रित यानी सहफसली खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस विधि से एक साथ दो फसलों की खेती होती है। इस खेती में किसानों को दोगुनी आय मिलती है वह भी एक साथ दो फसलों की खेती करते हुए। इसमें मौसम और मिट्टी का ध्यान रखते हुए आसानी से एक साथ दो फसलों की खेती की जा सकती है। इस मौसम में किसान आलू के साथ मक्का की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आलू और मक्का की मिश्रित खेती में आलू को मक्का के बीच-बीच में लगाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उसी खेत में आलू के अलावा राजमा और बाकला की भी खेती की जा सकती है।

इस तरह करें मिश्रित खेती- दो या दो से अधिक पसलों को एक ही खेत में और एक ही मौसम में उगाया जाता है तो उसे अंतर्वती या मिश्रित खेती कहते हैं। इससे खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण, खाद और उर्वरकों के प्रयोग में आसानी रहती है। साथ ही एक फसल दूसरी फसल के विकास और वृद्धि को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार आलू के साथ मक्का की सहफसली खेती करके मक्का फसल को बिना कोई क्षति पहुंचाए इसी जमीन से आलू की फसल लगाकर दोहरा लाभ कमाया जा सकता है।

खर्च कम, आमदनी ज्यादा- कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो इस खेती में जो खर्च होता है, उससे बहुत अधिक आमदनी हो जाती है। एक ही खेत में 3-4 क्विंटल तक आलू की पैदावार हो जाती है। इसी खेत में डेढ़ क्विंटल तक मक्का मिल जाता है। वहीं, किसान मक्का के साथ आलू या आलू के साथ राजमा की खेती कर सकते हैं या मक्का के साथ राजमा की खेती की जा सकती है।

एक खर्च में दोहरा लाभ

आलू के साथ मक्का की इंटरक्रॉपिंग की जाती है। इसमें आलू की खुदाई पहले हो जाती है, जबकि मक्का की कटाई बाद में होती है। इस खेती में एक ही खर्च में दोहरा लाभ मिलता है। खेत में एक ही बार खाद देना होता है, जिससे अच्छी पैदावार मिल जाती है। वहीं, आलू-मक्का या मक्का-बाकला की खेती में दो बार सिंचाई करने की जरूरत होती है।

खेत की उर्बरा शक्ति में इजाफा

अन्य फसलों की बात करें तो किसान आलू, मूली, मटर और राजमा की खेती एक साथ कर सकते हैं। इस मिश्रित खेती से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ ही खेतों में मक्का के साथ अन्य फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर हो सकता है। इन फसलों को बेचकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि मक्का की बुवाई करने से पहले खेत की गहरी जुताई जरूर करें। बुवाई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से 10-15 टन गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर दें। अधिक उपज लेने के लिए हाइब्रिड किस्म के बीजों को लगा सकते हैं।

इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो होगा नुकसान

अच्छी उपज के लिए कब और कैसे करें सरसों की फसल में किसान सिंचाई

भोपाल। अन्य फसलों की तरह सरसों की खेती में भी पानी की जरूरत होती है। पानी के बिना खेती से अच्छी उपज लेना मुश्किल है। इस बात का ध्यान रखें कि सरसों की खेती में कितनी बार और कब-कब सिंचाई करनी है। सिंचाई में पानी की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर सरसों की फसल खराब हो सकती है।

4-5 सिंचाई पर्याप्त- सरसों की खेती के लिए 4-5 सिंचाई पर्याप्त होती है। यदि पानी की कमी हो तो चार सिंचाई करनी चाहिए। इसमें पहली सिंचाई बुवाई के समय, दूसरी सिंचाई शाखाएं बनने के समय, तीसरी फूल आने के समय और चौथी सिंचाई फली बनते समय करनी चाहिए। दिन के हिसाब से देखें तो पहली सिंचाई बुवाई के साथ, दूसरी सिंचाई बुवाई के 25-30 दिन बाद, किसानों को तीसरी सिंचाई बोवनी के 45-50 दिन बाद और अंतिम सिंचाई बोवनी के 70-80 दिन बाद करनी चाहिए।

दाना पकते समय सिंचाई से मजबूत होगा दाना

अगर पानी की कमी न हो तो किसान सरसों में पांचवीं सिंचाई भी कर सकते हैं। कृषि एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर पानी उपलब्ध हो तो एक सिंचाई दाना पकते समय करनी चाहिए। यह सिंचाई बोवनी के 100-110 दिन बाद करनी लाभदायक होती है। ध्यान रखें कि सिंचाई फव्वारा विधि से करनी चाहिए। इसमें पानी की खपत कम होती है और फसलों को बराबर पानी मिलता है। इससे फसल की पूरी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। दाने भी बड़े और मोटे बनते हैं।

कीटों से सुरक्षा

सरसों की फसल को कीटों से बहुत नुकसान पहुंचता है। इसी में एक है पेन्टेड बग और आरा मक्खी, यह कीट फसल को अंकुरण के 7-10 दिनों में अधिक हानि पहुंचाता है। यह कीट फसल को पूरी तरह से चौपट कर देता है। इस कीट की रोकथाम के लिए एंडोसल्फान 4 प्रतिशत या मिथाइल पैराथियोन 2 प्रतिशत चूर्ण की 20 से 25 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। इससे सरसों को पेन्टेड बग और आरा मक्खी से सुरक्षा मिलती है।

अदरक की पैदावार बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल नाइट्रोजन खाद का

वैज्ञानिक विधि से अदरक की खेती किसानों को कर देगी मालामाल

भोपाल। जागत गांव हमार

अदरक की मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में अदरक का खूब इस्तेमाल किया जाता है, तभी किसानों भी अदरक की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। ऐसे में अगर आप किसान हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए कि अदरक की पैदावार को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि पैदावार बढ़ेगी तभी कमाई भी बढ़ेगी। अदरक की पैदावार बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल नाइट्रोजन खाद का होता है। लेकिन इस खाद को कब दें और उसकी डोज क्या हो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए।

अदरक की फसल में नाइट्रोजन की दो डोज जरूरी- अदरक की फसल में नाइट्रोजन की दो डोज को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दो डोज पर फसल की क्वालिटी और उपज निर्भर करती है। जो किसान अदरक की खेती कर रहे हैं, वे नाइट्रोजन की मात्रा को दो बराबर भागों में बांट लें। इसका पहला हिस्सा बिजाई के 75 दिन बाद और बाकी हिस्सा बिजाई के 3 महीने बाद डालना चाहिए। आप अदरक की बढ़त के लिए रोपाई के 4-6 सप्ताह बाद यूरिया जैसे नाइट्रोजन वाले उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदरक के लिए प्रति हेक्टेयर 75 किलो नाइट्रोजन की मात्रा देने की सलाह दी जाती है। खेत को तैयार करते समय प्रति एकड़ 25 किलो नाइट्रोजन (जिसके लिए 55 किलो यूरिया दे सकते हैं) की मात्रा दे सकते हैं। आप नाइट्रोजन खाद के अलावा जैविक खाद जैसे कि कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक की बेहतर उपज और क्वालिटी के लिए खेत की तैयारी के समय प्रति एकड़ 2-3 टन गोबर की खाद भी मिट्टी में मिला देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अदरक के खेत में जिंक की कमी है तो इसकी 6 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर डालने से उपज अच्छी मिलती है। जिंक की कमी पूरी करने के लिए खेत में 30 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि जब अधिक बारिश हो रही हो तो अदरक के खेत में यूरिया खाद या नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल न करें। इससे खाद का नुकसान होता है जबकि फसल को कोई फायदा नहीं मिलता। किसान को फिर से यूरिया खाद देने की जरूरत पड़ जाती है।

खेत में मल्चिंग से फायदा

अदरक के खेत में मल्चिंग से बहुत फायदा मिलता है। इसके लिए किसान खेत में हरी पत्तियां बिछा सकते हैं जिससे नमी के नुकसान के साथ ही मिट्टी के क्षरण से निजात मिलती है। अदरक का कंद लगाते वक्त मल्चिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। बुवाई के 40 और 90 दिन बाद फिर से मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं।

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर नीतियों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर साझा किए विचार

मप्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने ब्रांडिंग और सामुदायिक मॉडल

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर सामुदायिक मॉडल अपनाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग ने जलवायु सहनशीलता और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: मार्ग, चुनौतियां और नीति समर्थन विषय पर संवाद आयोजित किया। इस संवाद में कृषि, बागवानी और सतत विकास के विशेषज्ञों के साथ-साथ महिला किसान, स्वयंसेवी संगठन और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर नीतियों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर विचार साझा किए।

प्राकृतिक खेती के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जरूरी

राज्य नीति आयोग के सीईओ, ऋषि गर्ग ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। आंध्रप्रदेश के उप निदेशक हॉर्टिकल्चर, श्रीनिवासुलु ने सामुदायिक प्राकृतिक खेती के अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कम लागत और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से यह मॉडल किसानों के लिए अधिक व्यवहारिक बनता है।

नीतियों और मार्केटिंग पर चर्चा | अतिरिक्त सचिव बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रीति मैथिल ने कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पाद उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। इन्हें व्यावसायिक सफल बनाने के लिए बाजार से जोड़ने और मजबूत नीति समर्थन की आवश्यकता है। पद्मश्री डॉ. सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक और जैविक खेती के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए शून्य लागत प्राकृतिक खेती की तकनीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाकर इसे अधिक किसान-हितैषी बनाया जा सकता है।

महिला किसानों और सामुदायिक मॉडल पर जोर

प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, दीपाली रस्तोगी ने संवाद के दौरान विशेषज्ञों से सामुदायिक मॉडल अपनाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से इस मॉडल को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती को व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता में सुधार और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

नरवाई किसान के लिए समस्या, सुपर सीडर खाद के रूप में बदलकर बना देता है खाद

किसानों के लिए वरदान है सुपर सीडर मशीन, मिल रहा 40 प्रतिशत अनुदान

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए शासन द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसमें किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी का उदाहरण है सुपर सीडर मशीन। सुपर सीडर ट्रैक्टर के साथ जुड़कर कार्य करने वाला ऐसा यंत्र है जो नरवाई की समस्या का निदान करने के साथ ही साथ बोवनी भी करता है। जो किसान धान की खेती के बाद गेंहू और चने की बोवनी करते हैं उनके लिए यह अत्यंत उपयोगी है।

सुपर सीडर धान अथवा अन्य किसी भी फसल के डंठल जिसे नरवाई कहा जाता है उसे आसानी से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला देता है। इसके उपयोग से नरवाई को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे एक और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है वहीं दूसरी ओर मिट्टी के ऊपरी परत के उपयोगी जीवाणुओं के जीवन की रक्षा भी होती है। सुपर सीडर से नरवाई वाले खेत में सीधे गेहूं एवं चने

अथवा अन्य फसल की बोनी की जा सकती है। इसके उपयोग से किसान को नरवाई की झंझट से मुक्ति मिलती है। जो नरवाई किसान के लिए समस्या, है उसे सुपर सीडर खाद के रूप में बदलकर वरदान बना देता है।

किसानों को दिया जा रहा है अनुदान

विदिशा जिले के किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के उप संचालक केएस खपेडिया ने बताया कि जिले के कृषि अभियांत्रिकी विभाग में सुपर सीडर उपलब्ध है। शासन की योजनाओं के तहत किसान को सुपर सीडर खरीदने पर 40 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। सुपर सीडर सामान्य तौर पर एक घण्टे में एक एकड़ क्षेत्र में नरवाई नष्ट करने के साथ बोवनी कर देता है। गेहूं के बाद जिन क्षेत्रों में मूंग की खेती की जाती है वहाँ भी सुपर सीडर बहुत उपयोगी है। हार्वेस्टर से कटाई के बाद गेहूं के शेष बचे डंठल को आसानी से मिट्टी में मिलाकर सुपर सीडर मूंग की बोवनी कर देता है। सुपर सीडर के उपयोग से जुताई का खर्च बच जाता है। नरवाई नष्ट करने व जुताई और बुवाई एक साथ हो जाने से खेती की लागत घटती है। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर हैं उनके घर के शिक्षित युवा सुपर सीडर खरीदकर एक सीजन में एक लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं।

पांढुर्ना में सीसीआई ने किया कपास खरीदी का शुभारम्भ

पांढुर्ना। पांढुर्ना कृषि उपज मंडी में गुरूवार को भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा कपास खरीदी का शुभारंभ किया गया। मंडी प्रांगण में आए पहले किसान गोपाल घोड़े, पांढुर्ना का 20 क्विंटल कपास 7421 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया। इस अवसर पर प्रभारी मंडी सचिव राजाराम उइके, सीसीआई केंद्र प्रभारी प्रितेश सुरंजे, मंडी कर्मचारी, व्यापारी एवं किसान उपस्थित थे। मंडी सचिव उइके ने बताया कि मंडी प्रांगण में दो किसानों से 43 क्विंटल 80 किलो कपास की खरीदी की गई। मंडी प्रांगण में कपास की नीलामी सुबह 11 बजे से डेढ़ बजे तक की जाएगी। कपास बेचने आए किसानों को आधार कार्ड की फोटो कॉपी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, खसरा, पावती,गिरदावरी बी-1 ,बी 2, एमपी किसान एप अथवा सारा एप में कृषक के नाम के साथ कृषि भूमि व कपास फसल की पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

फसल को सुखाकर व साफकरके लाएं

पांढुर्ना मंडी में कपास नीलामी के लिए इस वर्ष पालीवाल जिनिंग एन्ड प्रेसिंग से अनुबंध हुआ है। किसानों से अपील है कि वे अपनी कपास फसल को सुखाकर एवं साफ करके लाएं। पीला, कौड़ीयुक्त व 12 फीसदी से अधिक नमी वाला कपास सीसीआई द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। सीसीआई द्वारा कपास की नमी के आधार पर कपास खरीदी के भाव तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं- 8 फीसदी नमी- 7421, 9 प्रतिशत नमी - 7346। 79 ,10 प्रतिशत नमी- 7272.58 ,11 प्रतिशत नमी - 7198.37 और 12 प्रतिशत कमी -7124.16 रुपए क्विंटल तय किए गए हैं। गत वर्ष सीसीआई द्वारा पारसनाथ जिनिंग प्रांगण में कपास की खरीदी की गई थी, जो शहर से बहुत दूर थी, लेकिन इस वर्ष कपास की खरीदी मंडी प्रांगण में की जा रही है।

कुपोषण दूर करने केवीके द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण

मंदसौर। कृषि विज्ञान केन्द्र, मंदसौर द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन गत दिवस किया गया। इस कार्यक्रम के समापन पर डॉ. आईएस तोमर, अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर ने कहा कि पोषण वाटिका एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ तथा दैनिक आहार में सहजन एवं आंवले के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दी। केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. जीएस चुंडावत ने समूह के माध्यम से आंवले के उत्पाद तैयार कर आय सृजन के बारे में जानकारी दी। प्रमुख प्रशिक्षक डॉ. एसपी त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा आंवला के मूल्यवर्धित विभिन्न उत्पादों के बारे में विस्तृत रूप से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक

जानकारी दी, जैसे कि आंवला लड्डू, मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला सुपारी, आंवला पाउडर, त्रिफला चूर्ण एवं आंवला शरबत को बनाना सिखाया गया। प्रशिक्षण में जिले की महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका सम्मिलित होकर प्रशिक्षण का लाभ लिया। जिससे कुपोषित बच्चों को खिलाकर कुपोषण को दूर कर सके।

'एक जिला-एक उत्पाद' की तर्ज पर लगाई जाएगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट : मंत्री कुशवाहा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर उद्यानकी फसलों की प्रोसेसिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जाएगी। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने नागपुर में आयोजित एग्रो विजन राष्ट्रीय कृषि मेले में आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना जिला और संभाग लेवल पर हो जाने से उत्पादक किसानों को उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। मंत्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में 20 वर्षों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। खेती-किसानी को सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में कृषि उत्पादन बड़ा है। किसान भाई परंपरागत खेती के स्थान पर कैश क्रॉप के प्रति आकर्षित हुए हैं, उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास है कि उद्यानकी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को फसल का सही दाम मिल सके। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केटिंग का काम प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री कुशवाहा ने नागपुर में पैदा किए जा रहे हैं ऑर्गेनिक संतरे की फसल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी संतरे का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। संतरे की फसल को और अधिक

मध्यप्रदेश में नागपुर की तर्ज पर होगी संतरे की खेती

बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के किसानों को नागपुर स्टडी टूर पर भेजा जाएगा, जिससे किसान भाई ऑर्गेनिक संतरे की उत्पादन प्रक्रिया को देख और समझ सकेंगे।

शुजालपुर के किसान देवेंद्र परमार दूध-घी और खाद बेचकर सालाना कमा रहे 50 लाख

खेत में गोबर से बनाई सीएनजी, इससे चला रहे ट्रैक्टर बाइक, कक्षा आठवीं पास को गोपाल रत्न पुरस्कार

डा. नारायण सिंह परमार

शुजालपुर। जागत गांव हमार

शुजालपुर के रहने वाले युवा किसान देवेंद्र परमार को दिल्ली में गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान बेस्ट डेयरी फार्मर कैटेगरी में देसी पशुओं की नस्ल सुधार के लिए दिया गया। देवेंद्र ने अपने खेत में बायोगैस संयंत्र लगा रखा है, इससे वे सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) बनाते हैं। इसी की मदद से अपनी कार, बाइक और ट्रैक्टर चलाते हैं। इससे पेट्रोल, डीजल पर होने वाला खर्च बच जाता है। यही नहीं, वे केंचुआ खाद के साथ बिजली भी पैदा करते हैं। जागत गांव हमार इस अंक में पाठकों को पटलावदा के रहने वाले देवेंद्र परमार से मिलवा रहा है। इन्होंने अपनी 2 हेक्टेयर यानी 10 बीघा जमीन पर बीते 6 साल से रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया। वे दूध, घी, केंचुआ खाद बेचकर सालाना 50 लाख रुपए कमा रहे हैं।

रोज 100 यूनिट बिजली का उत्पादन

देवेंद्र बताते हैं, मेरा डेयरी का कारोबार है। आसपास के गांव से दूध खरीदकर लोडिंग वाहन, कार और ट्रैक्टर के जरिए लाते थे। रोज करीब तीन हजार रुपए का डीजल और पेट्रोल डलवाना पड़ता था। इस खर्च से परेशान होकर अपने गोबर गैस संयंत्र को बायोगैस प्लांट में तब्दील कराया। बिहार से आए इंजीनियर ने प्लांट लगाने में मदद की। इसमें 25 लाख रुपए की लागत आई। मेरे पास 10 बीघा जमीन भी है। इसमें पिछले 6 साल से रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। 168 दुधारू पशु हैं। रोजाना 40 क्विंटल गोबर जमा होता है। ऑटोमैटिक मशीन से गोबर 600 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में डाला जाता है। इससे रोज 100 यूनिट यानी 12 किलोवाट बिजली पैदा हो रही है। गोबर के वेस्ट से केंचुआ खाद बनती है। 300 किलो जैविक खाद 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। खाद को आसपास के गांवों के किसान ही ले जाते हैं।

महीनेभर में 4 लाख का प्रॉफिट

देवेंद्र ने कहा कि बायोगैस प्लांट से रोज 200 किलो गैस का उत्पादन हो रहा है। इसे सीएनजी के रूप में वाहनों को चलाने में इस्तेमाल करता हूं। खेत पर बनने वाली बिजली से ब्रांडेड दूध, घी और खाद की पैकिंग मशीन चलती है। रोजाना 500 लीटर दूध-घी से 30 हजार, केंचुआ खाद बेचकर तीन हजार और खुद के मवेशियों का 500 लीटर दूध बेचकर 4 हजार रुपए की कमाई होती है। इसके अलावा 1500 लीटर दूध सांची दुग्ध संघ भोपाल को भी बेचते हैं। बिजली के लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा रखा है। 20 कर्मचारियों के खर्च, प्रबंधन, देखरेख और चारे की व्यवस्था को काटकर महीनेभर में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है।

खाद बनाने का तरीका भी अलग

केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) के लिए दूसरे किसान निर्धारित साइज में बेड बनाते हैं। देवेंद्र ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि दस बीघा जमीन पर गोबर फैला है। हर कदम पर केंचुआ खाद है। मशीन से छानकर सूखा खाद और केंचुए अलग किए जाते हैं। सूखी खाद 10 और केंचुआ मिक्स खाद 50 रुपए किलो बिकती है। 50 किलोमीटर दूर तक के किसान इसके लिए एडवांस बुकिंग कराते हैं।

ऑटोमैटिक मशीनों से पूरा काम

देवेंद्र का कहना है कि पूरा काम ऑटोमैटिक मशीन की मदद से होता है। मवेशियों के लिए व्यवस्थित बनाए गए शेड में इस तरह नालियां और कंप्रेसर फिट किए गए हैं, जिससे गोमूत्र और गोबर ऑटोमैटिक ही प्लांट में मिनटों में चला जाता है। मवेशियों को दिया जाने वाला चारा काटने से लेकर दूध बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला दाना बनाने की मशीन भी खेत में लगा रखी है। चारा स्टोर करने भी मशीन लगी है।

कर्नाटक, ओडिशा से सीखने आते हैं किसान

कभी देवेंद्र खुद दूसरे प्रदेशों में जाकर कम लागत में पशुपालन के तरीके सीखते थे, आज हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों के किसान किसानी और पशुपालन की सीख लेने उनके पास आते हैं। देवेंद्र देसी गाय की ब्रीडिंग कर सालाना 20 बछिया बेचते हैं, बाकी अपनी गोशाला में ही रख लेते हैं। उनके पास देसी मालवा नस्ल की 33 गाय हैं। इसी तरह सायवल, गिर, थारपरकर, एच एफ, गिर क्रॉस ब्रीड के 168 पशु हैं, जिनमें 150 वयस्क हैं। दूध प्लांट में भी बायो गैस से सब काम होता है।

तीन श्रेणियों में दिया जाता है पुरस्कार

पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों, सहकारी समितियों, दूध उत्पादक कंपनियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिया जाता है। देवेंद्र परमार को सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, स्वदेशी मवेशी नस्लों का पालन करने, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) श्रेणी में इस पुरस्कार के चुना गया था। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के अवसर पर मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया।

MPIDC MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD. | MSME | MPSEDC

निवेशकों का बढ़ता विश्वास, क्षेत्रीय उद्योगों का संपूर्ण विकास

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

INVEST MADHYA PRADESH

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

फरवरी 2025, भोपाल

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश की गति को बढ़ाने के लिए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

की पहल पर क्षेत्रीय औद्योगिक विकास के लिए

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

का श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया जा रहा है।

नये निवेश से क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों की उन्नति के साथ युवाओं के लिए रोज़गार के नये अवसरों से नई राहें खुल रही हैं।

उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलूरु, कोलकाता में हुए निवेशकों के साथ इंटरेक्टिव सत्रों में कुल 2 लाख 76 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 3.28 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होंगे

निवेशकों को विशेष सुविधाएं और नीतियां-

सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश प्रोत्साहन योजना और कस्टमाइज़ पैकेज जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। नए निवेशकों को उद्योग मित्र नीतियों के साथ सरल और सुगम निवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है।

एक्सपोर्ट हब बनता मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से मध्यप्रदेश न सिर्फ औद्योगिक हब बन रहा है बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कनेक्टिविटी, उद्योग-अनुकूल नीतियां और मजबूत अधोसंरचना से मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि: पिछले वित्त वर्ष में 13,158 करोड़ रुपए के दवा उत्पादों का निर्यात। निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य: आने वाले तीन वर्षों में निर्यात को दोगुना करने का संकल्प, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी।

Website : invest.mp.gov.in

D-18040/24

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक: अरविंद मिश्रा, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)